

कोहका में बांस के पेड़ों में लगी भीषण आग



निवास, नवभारत। जिले के निवास थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कोहका में विगत दिवस एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहाँ गांव के निवासी डालचंद सेन के घर के बिल्कुल नजदीक स्थित एक विशाल बांस के पेड़ में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई।

बताया जाता है कि बांस के पेड़ों में लगी आग देखते ही देखते तेज लपटों के साथ बेहद विकराल रूप ले लिया और पूरा पेड़ धू-धू

कर जलने लगे।

ग्रामीणों ने किया प्रयास, फायर ब्रिगेड को दी सूचना

पेड़ में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया। आग को घर के इतने नजदीक देखकर आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए तत्काल अपने-अपने घरों से पानी के बर्तन और बाल्टियाँ लेकर खुद ही आग बुझाने

का साहसिक प्रयास शुरू कर दिया। इसके साथ ही सजग ग्रामीणों द्वारा फौरन दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई।

दमकल टीम की सूझबूझ से घरों तक पहुंचने से रुकी आग

आग की सूचना मिलते ही दमकल वाहन की टीम त्वरित मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक़त की,

जिसके बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते दमकल की टीम नहीं पहुंचती और आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो लपटें पास में बने रिहायशी मकान तक फैल जातीं। इससे पूरा घर आग की चपेट में आ सकता था और बड़ा धन-जन का नुकसान हो सकता था। दमकल और ग्रामीणों की त्वरित सक्रियता से एक बड़ी अनहोनी टल गई।

आजीविका मिशन के जरिए होगी पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग



► कलेक्टर ने माटी कला के साक्षक बलराम से की मुलाकात

मंडला। आधुनिकता की तेज रफ़्तार के बीच अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संजोए रखने वाले माटी कला के कुशल शिल्पकार बलराम चक्रवर्ती से मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे

ने उनके निवास पर पहुँचकर आत्मीय मुलाकात की। इस विशेष भेंट के दौरान कलेक्टर ने चक्रवर्ती द्वारा वर्षों से संरक्षित और विकसित की जा रही पारंपरिक माटी कला का नजदीक से अवलोकन किया और उनके अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर शैलेन्द्र चौधरी, एसडीएम मंडला

मंडला में पॉक्सो पीड़ित बच्चों को मदद के लिए 21 नए सपोर्ट पर्सन इम्पैनल

मंडला। महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति, मंडला ने जिले में पॉक्सो पीड़ित बालक-बालिकाओं को त्वरित सहायता देने के लिए 21 नए सपोर्ट पर्सन इम्पैनल किए हैं। इसके साथ जिले में कुल सपोर्ट पर्सन की संख्या 50 हो गई है। वर्तमान में बाल कल्याण समिति के समक्ष पॉक्सो के लगभग 70 प्रकरण लंबित हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 39 के तहत यौन अपराध पीड़ित बच्चों को कानूनी प्रक्रिया, चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्वास में मदद के लिए सपोर्ट पर्सन देने का प्रावधान है। जिला स्तरीय चयन

समिति की अनुशंसा और अपर कलेक्टर के अनुमोदन के बाद 21 नामों का इम्पैनलमेंट आदेश जारी हुआ है। पुलिस सत्यापन और इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद इन्हें प्रकरणों में संलग्न किया जाएगा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जगेन्द्र गुप्ता ने बताया कि तीसरे चरण में आवेदन लेकर साक्षात्कार किए गए। सपोर्ट पर्सन पीड़ित और परिवार को भावनात्मक सहयोग देने के साथ कानूनी मदद, सुरक्षा, मुआवजा और गोपनीयता बनाए रखने का काम करेंगे। दिव्यांग बच्चों की विशेष जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

► विकास कार्य ठप होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

नारायणगंज, नवभारत। जनपद पंचायत नारायणगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत भावल में विभिन्न विकास कार्यों के अधूरे रहने और लंबित परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत कई विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भवाल में सांस्कृतिक



भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसकी प्रथम किस्त भी जारी हो चुकी है। भवन का मुख्य निर्माण कार्य तो

मूलभूत सुविधा के बिना भवन का समुचित उपयोग संभव नहीं है।

रंगमंच का निर्माण भी अधर में

इसी प्रकार विधायक निधि से स्वीकृत 2 लाख रुपये की लागत वाले रंगमंच निर्माण कार्य का भी अब तक शुभारंभ नहीं हो सका है। वहीं जनपद निधि से स्वीकृत 1 लाख रुपये के चबूतरा निर्माण कार्य की स्थिति भी लंबित बताई जा रही है।

आज तक नहीं पहुंचा ठेकेदार को नोटिस

ग्रामीणों के अनुसार इन सभी कार्यों की प्रथम किस्त जारी होने

मुआवजे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे चुटका के किसान

पुरानी सर्वे सूची रह करने की मांग, वर्ष 21 की जगह 2026 के रेट पर हो भुगतान

नारायणगंज/टिकरिया, नारायणगंज से चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र क्षेत्र तक बन रहे सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का विवाद गहरा गया है। परियोजना में अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा मौजूदा बाजार दर पर दिलाने की मांग को लेकर देवहारा और देवगांव के सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे से मुलाकात की और एक आवेदन सौंपा।

बताया गया कि सोपे गए आवेदन में प्रभावित किसानों ने पुरजोर मांग की है कि प्रशासन द्वारा वर्ष 2021 में तैयार की गई पुरानी सर्वे सूची को तत्काल निरस्त किया जाए और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार नए सिरे से जमीनी सर्वे कराया जाए। किसानों का कहना है कि प्रशासन उन पर 5 साल पुराने यानी वर्ष 2021 के रेट के आधार पर मुआवजा लेने का दबाव बना रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की हालिया घोषणा का हवाला देते हुए मांग की है कि वर्तमान प्रचलित



बाजार दर का चार गुना मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाए। इसके साथ ही पूर्व के सर्वे में छूटे हुए सभी पात्र किसानों को भी नई सूची में शामिल किया जाए।

निजी भूमि पर काम रोकने की चेतावनी—वर्तमान में सड़क चौड़ीकरण का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। विवाद से बचने के लिए ठेकेदार द्वारा फिलहाल केवल सरकारी भूमि पर ही कार्य कराया जा रहा है, जबकि अधिग्रहित की गई निजी कृषि भूमि

के टुकड़ों को बीच-बीच में छोड़ दिया गया है। मामले में प्रभावित किसानों का साथ दे रहे वरिष्ठ समाजसेवी पीडी. खैरवार ने स्पष्ट किया कि किसानों का रुख साफ है, जब तक पुरानी सर्वे सूची को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष सर्वे नहीं होता और उचित दर पर मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वे अपनी निजी भूमि पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने देंगे। किसानों ने जिला प्रशासन से इस संवेदनशील मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की है।

भुआ बिछिया के कटंगा में उपसरपंच लखन सिंह ने थामा भाजपा का दामन

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर शक्ति केंद्र की हुई बैठक, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुआ सामूहिक पौधरोपण

भुआ बिछिया। केंद्र एवं राज्य नेतृत्व के परिपालन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शक्ति केंद्र मांझीपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरही कटंगा में भाजपा की बैठक एवं जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. विजय आनंद मरावी, बिछिया भाजपा मंडल के महामंत्री व कार्यक्रम प्रभारी नरेश राजपूत, मंडल महामंत्री व शक्ति



केंद्र प्रभारी नरेश सर्वे और मंडल उपाध्यक्ष राकेश यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। वरिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रमों में भाजपा के

भाजपा की रीति-नीति से प्रभावित होकर ली सदस्यता

यह कार्यक्रम स्थानीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। ग्राम पंचायत कटंगा के उपसरपंच श्री लखन सिंह पन्ने ने भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियों और रीति-नीति से प्रभावित होकर डॉ. विजय आनंद मरावी एवं उपस्थित समस्त वरिष्ठ नेताओं के समक्ष भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सभी वरिष्ठ नेताओं ने स्कार्फ पहनाकर पार्टी में उनका आत्मीय स्वागत किया।

ग्राम पंचायत भावल में विकास कार्यों की लेटलतीफी पर उठे सवाल

► विकास कार्य ठप होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

नारायणगंज, नवभारत। जनपद पंचायत नारायणगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत भावल में विभिन्न विकास कार्यों के अधूरे रहने और लंबित परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत कई विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भवाल में सांस्कृतिक



भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसकी प्रथम किस्त भी जारी हो चुकी है। भवन का मुख्य निर्माण कार्य तो

मूलभूत सुविधा के बिना भवन का समुचित उपयोग संभव नहीं है।

रंगमंच का निर्माण भी अधर में

इसी प्रकार विधायक निधि से स्वीकृत 2 लाख रुपये की लागत वाले रंगमंच निर्माण कार्य का भी अब तक शुभारंभ नहीं हो सका है। वहीं जनपद निधि से स्वीकृत 1 लाख रुपये के चबूतरा निर्माण कार्य की स्थिति भी लंबित बताई जा रही है।

आज तक नहीं पहुंचा ठेकेदार को नोटिस

ग्रामीणों के अनुसार इन सभी कार्यों की प्रथम किस्त जारी होने

के बावजूद निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि पंचायत की बैठक में पंच, उपसरपंच एवं सरपंच द्वारा कमेटी के माध्यम से संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी

► लंबित कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

इस मामले को लेकर ग्रामीणों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ व्याप्त हैं। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास कार्यों में देरी से गांव के विकास की गति प्रभावित हो रही है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जनपद एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि स्वीकृत राशि, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

एमपीपीएससी में मेडिकल ऑफिसर बनीं अंजनियां की डॉ. सुमन

एसटी वर्ग में प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान, बस कंडक्टर पिता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मां के संघर्षों ने संवारा बेटी का भविष्य

बिछिया/अंजनियां। बिछिया विधानसभा के अंतर्गत अंजनियां क्षेत्र की प्रतिभाशाली आदिवासी बेटी डॉ. सुमन सैयाम का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और भाजपा पदाधिकारियों ने उनके निवास पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। शिशु रोग विशेषज्ञ व भाजपा नेता डॉ. विजय आनंद मरावी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. सुमन और उनके माता-पिता को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मिठाई भेंट कर बधाई दी। नेताओं ने कहा



कि डॉ. सुमन की यह सफलता पूरे जिले और समाज के लिए गर्व का क्षण है, जो अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

जानकारी अनुसार डॉ. सुमन सैयाम अंजनियां निवासी बस

बाद में इंदौर से उच्च शिक्षा हासिल की। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद माता-पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमन ने भी इस भरोसे को कायम रखते हुए परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डॉ. सुमन की इस सफलता की यात्रा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्व-सहायता समूहों का भी एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील योगदान रहा। उनकी माता निर्मला सैयाम की सुपुत्री हैं। एक सीमित संसाधनों वाले परिवार से आने वाली सुमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंजनियां में ही पूरी की और

कंडक्टर परदेशी सैयाम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निर्मला सैयाम की सुपुत्री हैं। एक सीमित संसाधनों वाले परिवार से आने वाली सुमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंजनियां में ही पूरी की और

गौराछापर में आयोजित हुआ क्लस्टर स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर

► कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर जानी समस्याएं

मंडला। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के प्रभावी समाधान एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत गौराछापर में क्लस्टर स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी जमीनी समस्याएं सुनीं तथा मौके पर मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके त्वरित

निराकरण के लिए निर्देश दिए। शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार के जन समस्या निवारण शिविरों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाकर शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने रेखांकित किया कि शासन की मंशा है कि ग्रामीणों को अपनी जायज समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासनिक अमला स्वयं उनके बीच पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं को समझकर हर करे।

मांग

पेंशनर्स ने महंगाई राहत, एरियर और कैशलेस बीमा विसंगतियों पर सरकार को घेरा

लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स का फूटा आक्रोश, मुख्यमंत्री के नाम निवास एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

निवास। मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स की लंबित और न्यायोचित मांगों का समय पर निराकरण न होने से पेंशनभोगियों और उनके परिवारों में गहरा असंतोष और निराशा व्याप्त है। इस गंभीर प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने लामबंद होकर एसडीएम एवं तहसीलदार निवास के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पेंशनर्स ने सीधा आरोप लगाया है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा घोषित तिथि से न तो समय पर महंगाई राहत दी जा रही है और न



ही आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल पा रहे हैं, जिसके कारण बुजुर्ग पेंशनर्स इस उम्र में अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं।

पेंशनर्स एसोसिएशन ने मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को अविलंब समाप्त किया

जाए, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच आपसी सहमति के फेर में पेंशन लाभों और महंगाई राहत में देरी का सबसे बड़ा कारण बनती है।

बुजुर्गों के हक पर डाल रहे डाका—पेंशनर्स एसोसिएशन ने आगे बताया कि पेंशनर्स को देय आर्थिक लाभ 4, 6, 8 महीने या साल भर की देरी से दिए जाते हैं। पेंशनभोगियों का कहना है कि एरियर का भुगतान न करना बुजुर्गों के हक पर डाका डालने जैसा है, अतः इसका समय पर भुगतान अनिवार्य किया जाए। छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों के निर्देशों के तहत कोरोना काल का रुका हुआ एरियर, छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर और 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज दर के साथ अविलंब जारी किया जाए।

इसके साथ ही पूर्व के विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों को मान्य करते हुए, 80 वर्ष के आयु पूर्ण होने पर मिलने वाले 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ को अब 79 वर्ष की आयु पूर्ण होने 80वें वर्ष में प्रवेश करती ही पर दिया जाए। विभाग के नियमित और कारगरत

कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी समय पर उपादान राशि का पूरा भुगतान किया जाए। पेंशनर्स संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भावुक अनुरोध किया है कि वे जीवन का अमूल्य समय शासकीय सेवा में देने वाले इन बुजुर्गों की संवेदनशील, न्यायोचित और जीवन-भरण से जुड़ी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। संघ ने चेतावनी भरे लहजे में मांग की है कि इन विसंगतियों का शीघ्र निराकरण कर बुजुर्गों को आर्थिक व मानसिक सबल प्रदान किया जाए।